Plan for Rural Development of Rajasthan

2119. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether plan to accelerate the pace rural development in Rajasthan during the next financial year has been formulated;

(b) if so, the details of the various welfare programmes/rural development schemes; and

(c) the total outlay, indicating contribution made each by the State/Central Government and outside Agencies World Bank etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (c) The major rural development programmes proposed to be implemented during 1993-94 in the State of Rajasthan are (i) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), (ii) Integrated Rural Development Programme (IRDP) with its sub-components, Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) and Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM), (iii) Desert Development Programme (DDP), (iv) Drought Prone Areas Programme (DPAP), (v) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP)/Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and (vi) Rural Sanitation Programmes.

The allocation for rural development programmes in the country has been substantially stepped up to Rs. 5010 crores in 1993-94 as compared to Rs. 3100 crores in 1992-93. However the State-wise outlay for 1993-94 under the above programmes have not yet been finalised. Assistance is received from outside agencies in respect of DWCRA and ARWSP. In case of DWCRA, the funding is equally shared between Government of India, State Government and UNICEF. In case of ARWSP, the projects with outside assistance are at consideration stage and UNICEF is likely to provide Rs. 9 crore during 1993-94 for guineaworm eradication programme.

ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास

2120. **श्री रामजी लाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई योजना मौजूद है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित कर रही संगठन/एजेंसी का नाम क्या है ;

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान 28 फरवरी, 1993 तक कुल कितने ग्रामीण श्रमिकों विशेषकर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ग्रामीण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराए गए और इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1993–94 के दौरान उपरोक्त श्रेणियों के कितने लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को मकान उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के भाग के रूप में इंदिरा आवास योजना चला रहा है । अब यह जवाहर रोजगार योजना का एक अंग है । कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों की मार्फत कार्यान्वित किया जाता है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(घ) 1993–94 के लिए लक्ष्य अभी तय नहीं किए गए हैं ।